7,500 करोड़ रुपये के 1,535 मेगावाट के प्रस्ताव 'नयी सौर ऊर्जा नीति' के अन्तर्गत स्वीकृत

1,350 मेगावाट हुआ सौर ऊर्जा उत्पादन

235 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप स्थापित

421 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पॉवर परियोजनाएं संचालित

720 करोड़ रुपये से 180 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयां स्थापित

उत्तर प्रदेश

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर

सराहनीय

सोमेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश को सोलर एनर्जी का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई अहम कदम उठाये हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 'नयी सौर ऊर्जा नीति-2017' लागू की गई है। योगी सरकार की योजना सोलर एनर्जी के जरिये प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही युवाओं को इन परियोजनाओं के जरिये रोजगार से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे निवेश से नौकरियों के नये रास्ते खुले हैं।

जगमग उत्तर प्रदेश

नयी सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत 1,535 मेगावाट के 7,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। 421 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पॉवर परियोजनाएं संचालित हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा इकाई स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी है। इस नीति के तहत अब गांव-गांव में सौर ऊर्जा की रोशनी अंधेरे को मिटा रही है।

सौर ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में बड़े निवेशक आगे आ रहे हैं। बीते साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 1,350 मेगावाट हो चुका है। कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। साथ ही कई नये निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रदेश सरकार को मिले हैं।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस

राज्य सरकार ने असीमित सम्भावनाओं वाले सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर नये द्वार खोले हैं। सोलर पार्क की स्थापना और थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस दिया गया है। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 100 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में छूट के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

सोलर प्लांट की स्थापना

योगी आदित्यनाथ सरकार के विशेष प्रयासों से जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर में लगभग एक दर्जन सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र चित्रकूट में सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। चित्रकूट के छीबों गांव में 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित किया गया है। साथ ही इसी गांव में 50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जा रही है। कानपुर देहात में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट और जालौन में 75 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया गतिमान है। राज्य के विभिन्न जनपदों में कई अन्य निजी कंपनियां भी सोलर प्लांट स्थापित कर रही हैं।

1.80 लाख सोलर पॉवर पैक संयंत्र की स्थापना

4,000 मेगावाट क्षमता की सौर परियाजनाएं बुन्देलखण्ड में संचालित

3,400 सोलर आरओ वाटर संयंत्र प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित

"सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में सौर ऊर्जा नीति लाई गई। इसके तहत सोलर पार्कों की स्थापना और थर्ड पार्टी बिक्री के लिए सौर ऊर्जा उपलब्धता के लिए ओपन एक्सेस दिया गया। लोगों को सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस' की व्यवस्था की गई। सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए जमीन में स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अतिरिक्त ऊर्जा को प्रोत्साहन

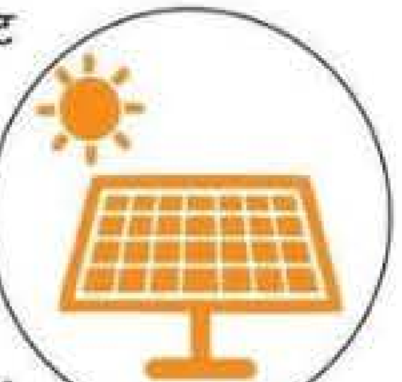

- पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ग्रामीण बाजारों में 25,569 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना
- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में 13,791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना
- वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा बचत हेतु 'ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018' लागू

अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर पार्क

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनपद झांसी की गरौठा तहसील में 3,023 एकड़ में विस्तृत 600 मेगावाट क्षमता के पॉवर प्लांट का शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर पार्क की स्थापना का लक्ष्य है। राज्य में सोलर पैनल, सोलर लाइट, सोलर बैटरी तथा सोलर कूकर आदि का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी दूर होने के साथ ही पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है।

जैव ऊर्जा नीति

- पैडी स्ट्रा आधारित बिजली की खरीद के लिए 20 वर्ष का क्रय अनुबंध
- राज्य विद्युत उत्पादन निगम के चालू विद्युत संयंत्रों में बायोकोल का भी फ्यूल के रूप में उपयोग
- उद्यमियों को कच्चे माल की उपलब्धता के लिए क्षेत्र का निर्धारण
- वेस्ट टू एनर्जी, बायोडीजल, बायो एथनॉल इकाइयों को केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य से सब्सिडी की सुविधा
- जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना तथा बायोमास संग्रह के लिए राजकीय, ग्राम पंचायत भूमि लीज पर लेने की सुविधा
- निजी काश्तकारों से भी 30 वर्ष तक की लीज पर भूमि लेने का विकल्प
- एफपीओ, ग्रामीण उद्यमियों तथा केंद्र की सतत योजना में चयनित उद्यमियों के साथ बायोमास आपूर्ति अनुबंध
- इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष तक विद्युत कर में शत-प्रतिशत छूट का प्रस्ताव
- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत 2,492 करोड़ रुपये का निजी निवेश आमन्त्रित।

किसान लगा सकेंगे संयंत्र

सहूलियत

ज्वाला अग्निहोत्री

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत किसान अपनी अनुपयोगी जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर अधिकतम दो मेगावाट की क्षमता के सौर उत्पादन पॉवर प्लांट लगा सकेंगे। स्थापित सौर पॉवर प्लांट का ग्रिड संयोजन 33/11 केवी के सब स्टेशनों पर किया जाएगा। ऐसे सभी सब स्टेशनों के पांच किलोमीटर की परिधि में अनुपजाऊ या बंजर जमीन पर सौर पॉवर प्लांट की स्थापना किसान कर सकेंगे।

20,177 सोलर पम्प पीएम कुसुम योजना में स्थापित

'जगमग' हो रहीं ग्रामीण सड़कें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लिए गये दूरगामी निर्णयों से अब गांवों के बाजार और सड़कें सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र लगाये गये हैं। किसानों को लाभ देने के लिये सिंचाई में उपयोगी 19,579 सोलर पम्प लगाए गये हैं। गांव में घर-घर तक 1.80 लाख से अधिक सोलर पॉवर पैक संयंत्रों की स्थापना ने गांव की तस्वीर बदल दी है।

39,360 सोलर स्ट्रीट संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित

हिन्दुस्तान मीडिया मार्केटिंग इनीशिएटिव